



2026:AHC:57764

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2023 सन् 2026

जगदीश यादव

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

—

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : सैयद अली इमाम

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

—

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सैयद अली इमाम और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 143 संख्या 2025, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi), 3(1) के अन्तर्गत, थाना एम्स, जिला गोरखपुर में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध अभिलिखित दोनों मामलों में जमानत पर है। उपरोक्त के अलावा उसका पांच आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण दिया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि, आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।
- आवेदक गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दर्शाए गए दोनों मामलों में जमानत पर है और उपरोक्त के अलावा उसके विरुद्ध पांच अन्य आपराधिक मामले भी अभिलिखित हैं, जिनका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक जगदीश यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/उन्हे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आरोपी विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आरोपी संबंधित न्यायालय की पूर्ण अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"